विधायक दल की बैठक बुलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता आलाकमान, क्योंकि 25 सितम्बर की घटना में उसकी किरकिरी हो चुकी

इसी के साथ पायलट खेमे को संतुष्ट करने के लिए नोटिस का जवाब देने वाले तीनों नेताओं पर कार्यवाही भी की जा सकती है, इस क्रम में रंधावा कई नेताओं से अकेले में बात कर चुके हैं

जयपुर, 22 मार्च (का.प्र.)। कांग्रेस आलाकमान इस समय भयभीत नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि सचिन पायलट ने जहां 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस अनुशासन समिति की ओर से तीन नेताओं को दिए गए नोटिस पर कार्यवाही नहीं होने का मुद्दा उठाया है तथा पायलट खेमे के एक विधायक ने भी यही मांग उठाने के साथ विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है, तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन 25 सितंबर के घटनाक्रम में मात खाने के बाद अब पार्टी आलाकमान वैसा ही घटनाक्रम दोहराना नही चाहता है।

यही कारण है कि एक ओर तो कांग्रेस आलाकमान पूरे मामले को लटका कर रख रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में चुनावी समय नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक आशंकित दिख रहे हैं कि यदि जल्दी ही इस पूरे मसले पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो दोनों खेमों के बीच इस अंतर्द्वंद का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल विधायक भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ज्यादा रहना चाह रहे हो, लेकिन अधिकांश विधायक सचिन पायलट को एडजस्ट किए जाने को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखा रहे है, लेकिन निर्णय तो पार्टी आलाकमान को भी लेना है।

इधर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने 25 सितंबर के घटनाक्रम को लेकर फिर से चर्चा शुरू की है, वही राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि विधायकों की मांग पर, जरुरत पड़ने पर वे विधायक दल की बैठक बुलाने की बात कर सकते हैं। यही कारण है कि रंधावा ने अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी सहित कई विधायकों से विधानसभा में अलग से चर्चा की है, ताकि विवादों का हल निकाला जा सके।

■ एक सुझाव यह भी आया है कि, सचिन पायलट को पी.सी.सी. या चुनाव कैम्पेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। पर यह मान्य नहीं होगा यह दिल्ली भी जानती है। फिर क्या यह केवल भ्रमित करने की चेष्टा है।

चर्चाओं में यह तो तय हुआ है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए। बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों में राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है, जिसमें करीब 10 मंत्रियों को सत्ता से हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है, लेकिन असली समस्या यह है कि आखिरकार सचिन पायलट को कहां एडजस्ट किया जाए। जानकारी के अनुसार सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद से कम पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी ओर 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान किसी भी स्थिति में फिर से वही विवाद नहीं चाहता। ऐसे में अब चर्चा यह है कि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और यदि वे इस बात पर तैयार नहीं हो, तो उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए। यदि सचिन पायलट इन दोनों में से किसी एक पद पर आ जाते हैं, तो वे टिकट बंटवारे में अपनी राय जाहिर कर पाएंगे और यदि उन्हें कोई पद नहीं मिल पाता है, तो फिर वह टिकट बंटवारे में अपनी राय नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उनके विधायकों को और समर्थकों को यह आशंका सता रही है कि कहीं उनके टिकट न काट दिए जाएं। इसी के साथ 25 सितंबर वाले मामले में तीनों नेताओं पर कार्यवाही कर दी जाए। इससे भी पायलट खेमे को खुश किया जा सकता है।

कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बदलाव को लेकर तो तैयार है, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने के लिए एक बार फिर विधायक दल की बैठक बुलाने को तैयार नहीं है। इसका कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरह का घटनाक्रम 25 सितंबर 2022 को हुआ, उसमें आलाकमान की किरकिरी हुई थी। उस घटनाक्रम के गवाह खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके है। ऐसे में उन्हें राजस्थान की स्थितियों का भी पता है कि यदि अब उसी तरह का विवाद छिड़ा, तो चुनावी वर्ष में गलत संदेश जा सकता है। ऐसे में विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बयान दे रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है।

अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच का विवाद अब नहीं खींचा जा सकता। ऐसे में अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान किस तरह से सचिन पायलट खेमे को चुनाव से पहले संतुष्ट करेगा, क्योंकि यह बात पार्टी आलाकमान और पार्टी के विधायक अच्छी तरह जानते हैं कि सचिन पायलट को यदि चुनाव तक इसी स्थिति में रखा गया, तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कर्नाटक में भाजपा का एक और कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के लिए स्थिति खुशनुमा नहीं है। ए.आई.सी.सी. अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले लोकसभा चुनाव में हराने में भाजपा की मदद करने वाले नेता बाबूराव चिंचान्सुर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछले लोकसभा चुनाव में हराने में भाजपा की मदद करने वाले नेता बाबूराव चिंचान्सुर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार की उपस्थिति में बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इस स्थिति में कोई अच्छी बात है तो वह यह कि चुनावों की घोषणा से ठीक पहले भाजपा नेता का कांग्रेस में शामिल होना विपक्षी पार्टी (कांग्रेस) के लिए उत्साहजनक है जो कि चुनाव प्रचार में ऊर्जा और आक्रामकता दिखा रही है।

कोली-कब्बालिगा समुदाय के एक प्रमुख नेता का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए एक करारा झटका है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद ना के बराबर थी। सोमवार को यह सार्वजनिक हो गया कि भाजपा के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और बताया जाता है कि उनका रूख कांग्रेस की ओर है। बाबूराव के लिए यह एक तरह से घर वापसी जैसा था क्योंकि चुनाव हारने के बाद वर्ष 2018 में वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। वह इससे पहले सिद्धारमैय्या सरकार में मंत्री थे।लेकिन, भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खड़गे को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई और अब अपनी पैतृक पार्टी में उनकी वापसी को विधानसभा चुनावों से पूर्व पार्टी को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। यह आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान बनने वाली स्थिति के लिए एक संकेत भी है। कांग्रेस ने देश के अन्य भागों के विपरीत कर्नाटक में भाजपा खेमे में जा चुके अपने नेताओं की घर वापसी कराने में सफलता अर्जित की है। कुछ हफ्ते पूर्व भाजपा विधायक दल के सदस्य पुट्टन्ना भी भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

■ कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा छोड़ने का सिलसिला और तेज हो गया है। भाजपा के बाबूराव चिंचान्सुर कांग्रेस में लौट आए। गौरतलब है कि, बाबूराव ने गत आम चुनाव में खड़गे को हराने में भाजपा की मदद की थी।

मैरिटल रेप अपराध है या नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मार्च। सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर 9 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एक विभाजित फैसला दिया था।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) डी. वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बैंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने बैंच को बताया कि इस केस के क्रमिक तर्क और सामान्य संकलन तैयार हैं। सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार का जवाब तैयार है और उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाना है।

■ सुप्रीम कोर्ट इस केस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है और मामले पर 9 मई को सुनवाई होगी।

बैंच ने कहा कि "केस को 9 मई 2023 के लिए लिस्ट किया जाए।"

शीर्ष अदालत ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित दायर कई याचिकाओं पर 16 जनवरी को केन्द्र सरकार से प्रत्युत्तर देने को कहा था।

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सी.जे.आई., डी. वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच को बताया कि इस मुद्दे के कानूनी के साथ ही सामाजिक मायने हैं और सरकार याचिकाओं के लिए अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहेगी।

'मोदी सिर्फ एक ही पार्टी के प्र.मंत्री लगते हैं तथा राहुल गांधी पढ़े-लिखे व समझदार हैं'

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कहा कि, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ मतदान नहीं होता इसका मतलब है स्वतंत्रता सभी संस्थानों की, विश्वविद्यालयों की और पुलिस की भी

नई दिल्ली, 22 मार्च। एक प्रमुख न्यूज चैनल इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने अपनी हालिया लंदन यात्रा के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी, कैसे भारत में संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है और देश में वर्तमान सरकार पर उनके विचार के बारे में बात की। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे जाने-माने राजनेताओं के परिवार से आते हैं और राहुल की वंशावली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत ध्यान मिलता है। पित्रोदा ने कहा है कि विपक्ष में राहुल गांधी ही एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं और बाकी सब मुख्य रूप से स्थानीय नेता हैं क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है।

सरकार के इस आरोप का जवाब देते हुए कि राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी से देश का अपमान किया, सैम पित्रोदा ने कहा कि वे उनकी (राहुल) टिप्पणी पर रक्षात्मक नहीं होने जा रहे हैं। सच्चाई को बाहर आने की जरूरत है। इस वैश्विक युग में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते... इसलिए आप क्या और कहां कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो भी कहते हैं वह वैश्विक हो जाता है।

सैम पित्रोदा ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्रता, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और पुलिस में स्वतंत्रता के बारे में है और यह केवल मतदान के बारे में नहीं है बेशक यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र वैश्विक जनता की भलाई के लिए है और भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 140 करोड़ लोग हैं। पित्रोदा ने कहा कि दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह वर्तमान में दबाव में है संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है झूठ का प्रचार किया जा रहा है।

आगे राहुल गांधी की विभिन्न टिप्पणियों पर बोलते हुए, सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं कई मंत्री, और मुट्ठी भर टीवी चैनल उनके पीछे होंगे न्यायपालिका से समझौता किया जा रहा है विश्वविद्यालय सहित संस्थान कमजोर हो गए हैं, झूठ फैलाया जा रहा है और इसे सुलझाना लोगों पर निर्भर है।

पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए, सैम पित्रोदा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप सरकार में आते हैं, तो आप केवल 30-40 प्रतिशत लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, बल्कि आप सभी के लिए एक प्रधानमंत्री हैं। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि अगर वह (पीएम मोदी) केवल एक समूह के हित के लिए काम करते हैं तो वह राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नहीं हैं वह एक पार्टी के पीएम हैं। हंगरी-अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस पर बोलते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि वह (सोरोस) उन लोकतंत्रों में निवेश करने में विश्वास करते हैं जो उनके लोकतंत्र के दृष्टिकोण के अनुसार काम कर रहे हैं ।

भारत ने पलटवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की है।

भारत ने ऐसा कदम अंतिम बार 2013 में तब उठाया था, और अमेरिकन दूतावास के बाहर सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिये गये थे। यह कार्यवाही अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागे की "बॉडी सर्च" तथा गिरफ्तारी के प्रतिकार स्वरूप की गई थी। ज्ञातव्य है कि देवयानी पर कथित रूप से वीज़ा-फ्रॉड तथा भारत के एक घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप थे।

10 साल पुराने इस खोबरागे प्रकरण के दौरान, भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कटौती कर दी थी तथा अमेरिका ने कानून-निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को भी भारत के शीर्ष अधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया था। इस समय, भारत सरकार इस दिशा में बढ़ती प्रतीत नहीं हो रही है। बुधवार को, अक्षय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने तो डिर्पार्टमैन्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड नैट ज़ीरो के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मीटिंग तक की। जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का प्रश्न है, उसने लंदन में "इंडिया हाउस" के आस-पास के इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी है। इसी बीच, भारतीय उच्चायोग ऐसी "जवाबी भ्रामक सूचना" देने की कोशिश कर रहा है कि "पंजाब सरकार राज्य में भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर रही है", जैसा कि पृथकतावादी ग्रुप "वारिस पंजाब दे" ने आरोप लगाया है। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोर्रे स्वामी ने ट्विटर पर पोस्ट डाली है, "मैं ब्रिटेन में रह रहे अपने मित्रों तथा खासतौर से पंजाब के भाई-बहिनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे इन सनसनीखेज झूठों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने "वारिस पंजाब दे" के उन तत्वों के खिलाफ कार्यवाही शुरु की है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं, खासतौर से अमृतपाल सिंह, जो इस संगठन का प्रमुख है। उन्होंने सिख समुदाय को आश्वस्त किया कि गिरफ्तार किये गये सभी लोगों के लिये कानूनी बचाव के संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित रखा जायेगा। उन्होंने दोहराया कि राज्य में सभी संचार सेवाएं, जिनमें मोबाइल टेलीफोन नैटवर्क तथा इन्टरनैट शामिल है, बहाल कर दी गई हैं तथा काम कर रही हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकम्प के कारण 50 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं

इस्लामाबाद, 22 मार्च (वार्ता)। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकम्प के कारण जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रांत में मंगलवार को आये तेज भूकंप के झटकों के कारण कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी और 44 अन्य घायल हो गये। अफगानिस्तान में भी भूकम्प से 4 लोगों की मौत हो गई तथा 80 अन्य लोग घायल भी हुये हैं।

खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल बासित ने बुधवार को स्थानीय मीडिया को बताया कि भूकंप से कम से कम 19 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मनसेहरा, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, हरिपुर, मर्दन, चित्राल, चारसद्दा और अन्य सहित देश के उत्तरी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किये गये थे।

■ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 13 लोगों की मौत हो गई तथा करीब 125 लोग घायल हुये हैं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किये गए, हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, साहीवाल, ओकारा और अन्य शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केन्द्र हिंदुकुश क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान के जुर्म शहर के पास 187 किलोमीटर गहराई में स्थित था। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने भूकंप की तीव्रता 6.8, जबकि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई है।

डॉन समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गये।

आंध्र में मु.मंत्री व पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बीच ही है, जो हमेशा की तरह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में बाधाएँ डालती रही है। मंगलवार को, "ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट इन्वैस्टमेन्ट्स- स्किल डवलपमैन्ट फॉर यूथ- एम्प्लॉयमैन्ट" पर राज्य विधानसभा में एक अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुये, मुख्यमंत्री रेड्डी ने पहली बार एक कथित स्किल डवलपमैन्ट घोटाले में सीधे ही नायडू का नाम लिया तथा उन पर पूरे पैसे को अप्रत्यक्ष रूप से बेनामी खातों में पहुँचा देने का आरोप लगाया।

नायडू के शासनकाल की फाइलें देखकर पता चलता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव तथा प्रधान वित्त सचिव पर एक स्किल डवलपमैन्ट प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिये दबाव डाला था तथा एक इकरारनामा करने के मामले में सारे नियम-कायदे ताक पर रख दिये गये थे। रेड्डी ने नायडू तथा उनकी सरकार हमला करते हुये, सीमेन्स की एक अंदरूनी रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने कथित रूप से घोटाले का सहारा लिया था।

रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री नायडू पर सीधा हमला, जिसका उद्देश्य उन्हें भ्रष्टाचार के मूल स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना था, करते हुये कहा, "विद्यार्थियों के कौशल विकास के नाम पर, तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख ने राजकोष को जमकर लूटा। 371 करोड़ रू. की राशि शैल कंपनियों के जरिये कहीं से कहीं पहुँचा दी गई।"

जगन मोहन रेड्डी ने आगे कहा, "मिस्टर चन्द्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के दोषी हैं। उनके मंत्रिमण्छल ने कहा कुछ था लेकिन वास्तविकता में किया कुछ और ही था। यह घोटाला आंध्र प्रदेश से शुरु होकर, विदेशों तक फैल गया था। उसके बाद, पूरा पैसा शैल कंपनियों के माध्यम से विदेशों से उनके खातों में आ गया था। स्किल डवलपमैंट प्रोग्राम में अनेक अनियमितताओं का हवाला देते हुये, मुख्यमंत्री ने कहा कि न तो डी.पी.आर. तैयार की गई थी, न प्रोजैक्ट का सत्यापन किया गया था और न निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। फिर भी सरकार जिसके प्रमुख नायडू थे, ने एग्रीमैंट कर लिया था तथा प्रोजैक्ट के लिये पैसा जारी कर दिया था।

तमिलनाडू की पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 4 की मौत

चेन्नई, 22 मार्च (वार्ता)। तमिलनाडु में कांचीपुरम जिला के कुरुविमलाई गांव में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट होने से बुधवार को कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी और 20 से अधिक लोग घायल हो गये। पुलिस मुख्यालय में से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस घटना में चार लोगों की मौत हुए हैं। मृतकों में पटाखा फैक्ट्री का मालिक सुदर्शन (31) भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कांचीपुरम के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।

■ इस हादसे में कम से कम 20 अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये।

खाली हाथ लौटे चीन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। चीन के राष्ट्रपति के प्रस्ताव एक शुरुआती विफलता बनकर रह गए और केवल रूस ने ही एक बयान जारी किया कि चीन के पेपर ने शांति का एक मार्ग उपलब्ध करवाया है। चीन के पेपर में ना तो यूक्रेन में रूस की कार्यवाही की भर्त्सना की गई यहां तक कि उसकी कार्यवाही को आक्रमण अथवा युद्ध तक नहीं माना गया।

शी के मॉस्को दौरे के बाद यूक्रेन में शांति स्थापना एक दूर की कौड़ी प्रतीत हुआ। पश्चिमी कूटनीतिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि शी का मॉस्को दौरा पश्चिमी देशों और उनकी प्रकट लोकतांत्रिक एवं उदार अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरोध में रूस-चीन संबंधों को मजबूत करने के लिए था और इन दोनों नेताओं ने पश्चिमी व्यवस्था के स्थान पर अपना अधिनायकवादी वैश्विक दृष्टिकोण थोपना चाहा। नि:संदेह, शी जिनपिंग का तीन दिवसीय मॉस्को दौरा आर्थिक सहयोग के कई समझौतों और रूस-चीन धुरी को मजबूती प्रदान करने के साथ सम्पन्न हुआ। दोनों परम मित्रों का मानना था कि यूरोप में नाटो के आक्रामक इरादों ने रूस एवं यूक्रेन पर युद्ध थोपा है। दोनों ने महसूस किया कि पश्चिमी देश अब लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाकर रूस और चीन को कमजोर करना चाहते हैं। तथापि, रूस के कई विशेषज्ञों और समीक्षकों तक का यह मानना है कि चीन का केवल एक ही मित्र हो सकता है, और वह है खुद चीन। उसका कूटनीतिक इरादा स्वयं के संकीर्ण उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और अपने देश का भला करना है। चीन के कोई सैद्धांतिक व अन्य स्थायी विचार नहीं हैं।

'क्रूड ऑयल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़कर अब 15.8 रू. लीटर हो गई है।"

उन्होंने कहा कि पिछले 305 दिनों में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 16.75 रू. लीटर की कमी आई है लेकिन इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिला। उन्होंने कहा, "ईंधन की बदलती हुई कीमतों की गति एक ही दिशा में रहती है? अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पैट्रोल और डीज़ल की कीमतें रात के 12 बजे बढ़ जाती हैं, लेकिन जब ये कीमतें गिर रही हैं तथा पिछले 305 दिनों में, कच्चे तेल की कीमतें 16.75 रू. लीटर गिर गई हैं तो इसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दिया जा रहा?"

गौरव ने उन प्राइवेट रिफाइनर्स की सूची की माँग की, जिन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदा था तथा पूछा कि उन्होंने यह किस भाव में खरीदा था। मीडिया रिपोर्टों का कहना है कि उन रिफायनर्स को कच्चा तेल बहुत रियायती दरों पर मिला था। उन्होंने इस तेल को रिफाइन किया वापस यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया तथा भारी लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का संबंध है, उन्हें केवल 2 डॉलर/बैरल ही मिले।

'मैंने कभी लंदन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वह अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं और उनकी जांच के लिए जे.पी.सी. के गठन की विपक्ष की मांग पर संसद की कार्यवाही तक अवरूद्ध की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जे.पी.सी. की हमारी मांग जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अमिताभ दुबे का भी परिचय करवाया जो मोदी से प्रतिदिन पूछे जाने वाले तीन प्रश्न तैयार करते रहे हैं।

जयराम ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से अब तक 99 प्रश्न पूछ चुके हैं और इनका समापन प्रश्न संख्या 100 से किया गया है। "हम इस श्रृंखला को मोदी से यह अंतिम प्रश्न पूछकर खत्म करते हैं कि क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग कर राष्ट्रीय हित में काम करेंगे।"

राहुल ने कहा कि मीडिया को यह पूछना चाहिए कि अडानी में ऐसा क्या है जो पूरी सरकार उनका बचाव कर रही है और संसद को नहीं चलने दे रही। उन्होंने कहा कि जे.पी.सी. में भाजपा का बहुमत होगा और उसका चेयरमैन भी भाजपा से ही होगा, लेकिन विपक्ष फिर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। जयराम ने कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 1992 और फिर वर्ष 2001 में जे.पी.सी. गठित किए जो का उदाहरण दिया। दोनों बार शेयर बाजार के घोटालों को लेकर जे.पी.सी. गठित की गई थी।

जयराम ने इस पर भी जोर दिया कि राहुल से क्षमा मांगने की मांग और अडानी के वित्तीय घोटालों के बीच कोई लिंक नहीं है।

राहुल के विदेश में दिए गए भाषणों को भाजपा द्वारा विकृत रूप दिए जाने को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और ना ही वह अडानी के मुद्दे को डायवर्ट करने की अनुमति देगी।

'जिले गठन के लिए वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है'

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा, जिले गठन के लिए लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 लागू होता है, लेकिन इसकी जरा भी पालना नहीं हुई है

जयपुर, 22 मार्च (का.सं.)। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि, जन आक्रोश अभियान के दूसरे चरण में राजस्थान के प्रत्येक जिले में 16 मार्च से अप्रैल मध्य तक जन आक्रोश घेराव किया जाएगा, जिसमें किसान कर्ज़ माफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध इत्यादि जनहित के मुददों को उठाया जाएगा और कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट का भाजपा द्वारा घेराव किया जाएगा।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, राजस्थान में सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार से जनता तंग आ चुकी है, कांग्रेस सरकार जनहित को ध्यान में नहीं रखती और अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रही है। किसी भी जब तक सीमा तय नहीं होती, तब तक किसी भी क्षेत्र को नहीं बनाया जाता, लेकिन यहां तो कांग्रेस सरकार सिर्फ लोक-लुभावन घोषणाए करने में लगी हुई है, कांग्रेस को ना जनता की और ना ही नियमों की परवाह है, एक ओर जहां स्थानीय कांग्रेसी नेता त्यागपत्र का नाटक करते है, वहीं दूसरी आलाकमान इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए है।

राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिलों का गठन किया है, जो कि राम लुभाया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने राजनीति प्रशासनिक दृष्टि से नियमों को पूरा नहीं करते हुए कार्य किया है। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अनुसार सरकार को जिला बनाने का अधिकार तो है लेकिन सीमाओं का निर्धारण आवश्यक है। राठौड़ ने कहा कि, सीमाओं का निर्धारण जब हुआ ही नहीं तो जिलों की घोषणा कैसे की जा सकती है, सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसका उदाहरण कुचामन-डीडवाना में से जिला किसको बनाया जाए? अब राजस्थान का पर्यटक पूछता है कि राजस्थान की राजधानी कौनसे जिले में है, दूदू और खेडली को ग्राम पंचायत से सीधे ही जिला बना दिया, तहसील से उपखंड बनते देखा, लेकिन ग्राम पंचायत से सीधे ही जिला बनना कांग्रेस की किस भावना को दर्शाता है। जबकि 7 ऐसे शहर हैं जो जिले की मांग को लेकर पिछले 4-5 दिनों से बंद चल रहे है और कांग्रेस द्वारा नियमों के विपरीत 5 पंचायतें भी बना दी गई हैं, जो नियम के विरूद्ध हैं। अब भाजपा का जनहित में लगातार संघर्ष जारी रहेगा।

■ राठौड़ ने कहा, कांग्रेस के मंत्री व विधायकों की धमकियों के चलते की गई नए जिलों की घोषणा।

■ उन्होंने यह भी कहा कि, भाजपा डॉक्टरों से अपील करती है कि, लोगों की जिन्दगी बड़ी अनमोल है, मरीजों का ईलाज जारी रखना चाहिए।

राठौड़ ने कहा कि, चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्व में चल रही चिरंजीवी योजना के 60 प्रतिशत क्लेम प्राइवेट अस्पतालों में होते है, जो अधिकांश बंद हैं, राजस्थान में आज अराजकता का माहौल बना हुआ है, राज्य में जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनमें निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, चिरंजीवी योजना के नाम पर राजस्थान में भ्रष्टाचार-हेराफेरी हो रही है। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि यदि अस्पताल 1 घंटा भी बंद रहता है तो कई जिंदगियां जा सकती है, कांग्रेस सरकार को चिकित्सा कर्मियों से संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। यदि सरकार चिकित्सकों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करेगी तो भाजपा चिकित्साकर्मियों का निश्चित रूप से सहयोग करेगी। हम डॉक्टरों से भी अपील करते है कि जिंदगी बड़ी अनमोल है, मरीजों का ईलाज जारी रखना चाहिए। राजस्थान सरकार निश्चित ही पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, जहां ब्लड बैंक से कुत्ते खून पी जाते हैं, किसानों की जमीने नीलाम हो जाती हैं, मुख्यमंत्री जीपीएफ लागू करने की घोषणा करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है, राजस्थान सरकार में पूर्व में हुई घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई और मुख्यमंत्री ने कहा था रिफाइनरी को अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कार्य ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

राठौड़ ने कहा कि, राजस्थान में कांग्रेस सरकार अब इस हद तक गिर चुकी है कि जिन वीर सैनिकों ने देश के लिए जान न्यौछावर करदी, ऐसे सैनिकों की वीरांगनाओं द्वारा जब मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखती है तो वीरांगनाओं को चोटी पकड़ कर खींचा जाता है। अब इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार को जनता ही देगी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, जिलास्तर पर होने वाला जन आक्रोश घेराव भरतपुर में 16 मार्च को हो चुका है और अन्य सभी जिलों की रूपरेखा बनकर तैयार है। प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी, मीडिया पैनेलिस्ट सुरेश गर्ग भी मौजूद रहें।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908